एक नयी गैर मौद्रिक, बाज़ार एवं मूल्याङ्कन रहित, सुख केंद्रित, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था

कांसेप्ट -प्रेमजीत सिरोही
लेखक -अम्बरीश मिश्रा

प्रस्तावना

प्रत्येक मनुष्य पसंदीदा शिक्षा, पसंदीदा रोजगार, पसंदीदा उत्पादों / सेवाओं और पर्याप्त आराम पाने की आकांक्षा रखता है। वह भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना या किसी अन्य को शोषित किये बिना। और इसके लिए एक प्रणाली की आवश्यकता होती है, यह सब सुव्यवस्थित रूप से सृजन और वितरण करने के लिए, ताकि सभी नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। यह श्वेत पत्र, इसी को संभव बनाने के लिए एक नए अर्थशास्त्र का एक वैचारिक ढांचा प्रस्तुत करता है।

हमने पिछले लेख में उल्लेख किया कि खुशहाल जीवन के कारकों का अव्यवस्थित एवं अनुचित आयोजन व वितरण सभी प्रकार की समस्याओं जैसे नकारात्मकता ,प्रतिस्पर्धा, हिंसा, ईर्ष्या, अत्यधिक लालच, भ्रष्टाचार, अपराध, आपसी झगडे आदि की ओर ले जाते हैं। हमने यह जानने की आवश्यकता पर जोर दिया कि मानव कल्याण के हमारे प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। हमने यह पाया कि आज तक के दर्शन में मनुष्य की जो अवधारणा रखी गयी है और उससे प्रेरित होकर जिस तरह का अर्थशास्त्र उपजा, उसके कारण अर्थशास्त्र के अब तक के सभी मॉडलों ने वांछित परिणाम नहीं दिया। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अर्थशास्त्र की प्रकृति को गहरे से पहचानें।

बाजार में धन की अनिवार्यता, क्यों अन्याय पैदा करती है?

आर्थिक प्रक्रिया उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की मांग के साथ शुरू होती है। वर्तमान में हमारे पास उत्पादों और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था है। यह एक प्रणाली है जिसमें उत्पादन और कीमतें निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत से उत्पाद एवं श्रम का मूल्याङ्कन होता है। बाजार के सभी संसाधनों को दुर्लभ माना जाता है ! फ्रीमार्केट में । हम अपनी निजी संपत्ति और श्रम के स्वैच्छिक विनिमय में संलग्न हैं। उद्यमी मुनाफे से प्रेरित होते हैं और इसलिए उच्च लागत दक्षता (cost efficiency) प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक निर्णय हमेशा इस बात से निपटते हैं कि संसाधनों को कैसे आवंटित या (उपयोग) किया जाए जिससे मुनाफा बढे।

तो उद्यमी मुनाफे से प्रेरित क्यों हैं ?

अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। धन हमें वांछित संसाधन, उत्पाद और सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार देता है। यदि आपके पास अधिक धन है , तो जाहिर है आप अधिक शानदार वस्तुओं व सेवाओं, सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अधिक से अधिक पूंजी पर नियंत्रण करके हम स्वयं को,अपने परिवार को, अपनी कंपनियों को, अपने राष्ट्र को और अधिक सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक धन आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह एक प्रतिस्पर्धी ढांचा है जहाँ संसाधन दुर्लभ माने गए हैं। आगे की खोजें और निर्माण भी पूँजी द्वारा ही संभव हैं। यदि आप पूँजी पर अधिक पकड़ नहीं रखते हैं, तो आप पिछड़ जायेंगे। किसी अन्य के पास ज़्यादा अधिकार होगा, आपके पास नहीं होगा। और ऐसे में आप दुसरे पर आश्रित हो जाएंगे, दास होने पर मजबूर हो जायेंगे, क्यूंकि उन संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी पर दुसरे का अधिकार होगा। स्वयं को श्रृंखला में श्रेष्ठ बनाने की यह प्रक्रिया जारी है क्योंकि प्रतिस्पर्धी ढांचा निरंतर असुरक्षा का भाव पैदा करता है ।

प्राथमिक प्रेरणा तो यह है की हम स्वयं के जीवन को और अपने प्रियजनों के जीवन को अधिक आरामदायक और अधिक आनंदमय बनाएं। लेकिन एक प्रणाली जिसमें यह सब करने की पूर्व शर्त पैसा है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा से धन एकत्र करना एक बहुत

ही स्वाभाविक परिणाम है। अब आइये इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से जानते हैं की मौजूदा अर्थशास्त्र के रहते सब लोग एक साथ धनी एवं समृद्ध क्यों नहीं हो सकते।

आर्थिक नीति जो गरीबी को बरकरार रखती है

सरकारें अपने नागरिकों को समृद्धि प्रदान करने में सक्षम क्यों नहीं हैं ? इतने सारे बेरोजगार लोग और कम वेतन वाले लोग क्यों हैं ? मौजूदा अर्थशास्त्र के रहते हम सब अमीर क्यों नहीं हो सकते ?

हमारे पास रोज का अनुभव है कि हमें बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है । हमारे अभी तक के अर्थशास्त्र में मूल नियम यह है कि हमें वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए, पहले धन अर्जित करना होगा। हमारे अर्थशास्त्र ने एक पूर्व शर्त रखी कि नागरिक वस्तुओं और सेवाओं का लाभ केवल तब उठा सकता है यदि उसके पास पैसा है। हम यह भी जानते हैं कि, अधिकांश आबादी (लगभग 90%) के पास इतना पैसा नहीं है ,कि वे अपनी इच्छा के अनुसार खरीद कर सकें।

पैसे की कमी के कारण, हम वस्तुओं और सेवाओं की ख़रीद के लिए बाजार में अपनी मांगों को रखने में सक्षम नहीं हैं । जब हम पूरी मांग नहीं करते हैं तो बाजार पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करता है । जब बाजार पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की ओर नहीं बढ़ता है तो पर्याप्त रोजगार कभी उत्पन्न नहीं होता है । पर्याप्त रोजगार के अभाव में , हमारे हाथ में पर्याप्त धन अर्जित करने के अवसर नहीं होते हैं । और पर्याप्त आय के बिना, हम अपनी मांगों को कभी भी बाजार में नहीं रख पाते हैं । और यह दुष्चक्र चलता रहता है । **बाजार में भरपूर मांग हो पाना पैसे की शर्त द्वारा सीमित है । यह मूल नियम आर्थिक विकास को बाधित करता है ।** आर्थिक विकास अन्य कारणों द्वारा होता ज़रूर है जैसे कि कानूनी ढांचे में सकारात्मक सुधार, विनिमय की गति में वृद्धि होना ,इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, तकनीकी विकास आदि । लेकिन वे कारक कभी भी अर्थशास्त्र के मूल आधार को लांघ नहीं सकते । मूल आधार यह है कि आप बाजार में मांग पैसे की उपस्थिति में ही कर सकते हैं । उत्पादों और सेवाओं को केवल अपनी आय के अनुसार ही भोग सकते हैं । आपको क्रेडिट ऋण की पेशकश की जा सकती है (आपके क्रेडिट मूल्य के आधार पर) लेकिन बैंक आपको खुली छूट नहीं देते हैं क्योंकि आपको ब्याज के साथ ऋण राशि वापस करनी होती है ।

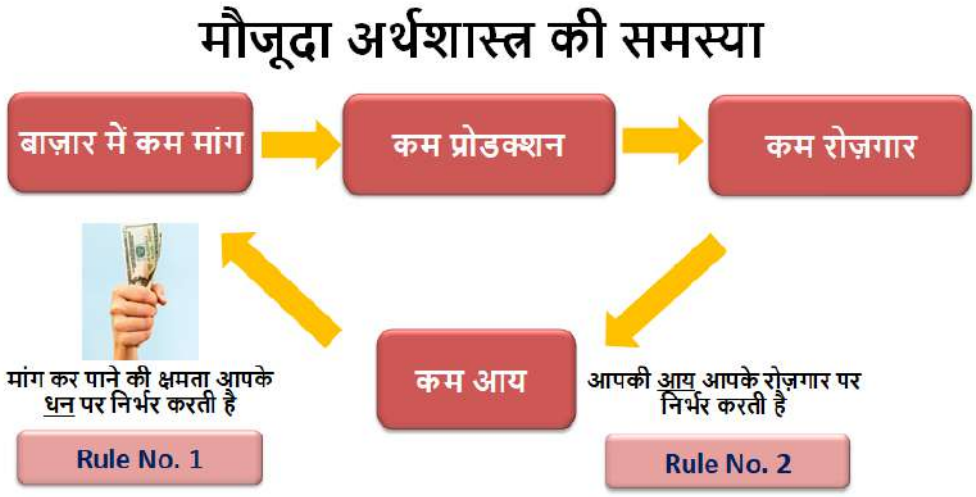

उपरोक्त आरेख को देख कर हम समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि पैसे की शर्त द्वारा सीमित है ,अवरुद्ध है । आप अपनी आय से अधिक नहीं ख़रीद सकते हैं और आपकी आय का एक हिस्सा बचत यानि भविष्य की सुरक्षा के लिए उपयोग किया

जाएगा । यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से एक पैसा भी नहीं बचाता है , फिर भी वह पूरी तरह से मांग करने में सक्षम नहीं है । और हम जानते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ की सभी को मांग करने की पूरी पूरी क्षमता रही हो ।

अर्थशास्त्र के बाकी नियमों को साइड कर , यदि हम केवल इस नीति के प्रभाव को अलग से निरीक्षण करते हैं , तो हम यह पाएंगे की जब तक मांग का अधिकार पैसे पर टिका है, तब तक उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग नहीं हो सकती । इसका मतलब है कि जब तक यह नियम बरक़रार है, हमारे पास बड़े सामाजिक स्तर पर पर्याप्त रोजगार कभी नहीं हो सकता है । कोई भी सरकार रोज़गार का केवल वायदा कर सकती हैं, वास्तव में दे नहीं सकती । क्योंकि आप बाजार में पैदा तो तभी करेंगे जब ख़रीदनेवाला कोई हो , और ख़रीदनेवाला कैसे आएगा जब रोज़गार ही नहीं है । और रोज़गार कैसे हो जब बाजार में पर्याप्त उत्पादन ही न हो रहा हो । और पर्याप्त उत्पादन क्यों होगा जब भरपूर मांग ही नहीं है । **तो मांग करने के अधिकार को धन से जोड़ने से ये सारी समस्या आ रही है ।**

अर्थशास्त्र का मूल विरोधाभास

मांग के लिए धन की अनिवारीयता से हम आर्थिक गतिविधि को जड़ से अवरुद्ध कर रहे हैं । और दूसरी तरफ बाहरी नीतियों से हम लोगों तक धन पहुँचाना भी चाहते हैं ताकि आर्थिक गतिविधि बढे ,खुशहाली बढे । आर्थिक समृद्धि का मतलब ही यही होता है की समाज में सबके लिए रोजगार हो और उस रोजगार से जनित सुख सुविधाओं को समाज भोग भी रहा हो । सरकार और अर्थशास्त्री, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां बनाते हैं, जैसे की सब्सिडी देना, कर माफ़ी, टैक्स रिफॉर्म्स ,ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में कमी, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा तंत्र, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ,शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि, हेल्थकेयर सुविधाओं में वृद्धि इत्यादि । अगर इस तरह की थोड़ी अच्छी नीतियों को ला पाए तो कुछ हदतक इन बाहरी उपचारों से गरीबी की मार को ज़रूर हल्का फुल्का कम किया जा सकता है, परन्तु हम गरीबी और असमानता को जड़ से हटा नहीं सकते । हम कुछ गरीब को मरते मरते शायद बचा भी लें लेकिन वास्तव जीवन नहीं दे सकते, क्यूंकि मूल ढांचा तो असमानता के लिए ही बना है । इन नीतियों के दूसरे दुष्परिणाम भी होते हैं जिन्हे बेअसर करना आसान नहीं।और यह उपलब्धि भी कैसे हो जब तक शिक्षित, बुद्धिमान, संवेदनशील नीति निर्धारक राजनैतिक नेत्रित्व तक नहीं पहुँचते ? और एक प्रतिस्पर्धी समाज में, जिसमें पैसे का बल काम करता है, ऐसे लोग पहुंच भी कैसे सकते हैं ?और इक्का दुक्का पहुँच भी गए तो, तो वे ऐसा क्या समाधान दें रहे हैं जिससे मूलभूत गरीबी और उससे जन्म लेने वाले युद्ध समाप्त होंगे ? आर्थिक असमानता और उसके दुष्प्रभावों को कैसे रोक सकते हैं ? इन छोटे मोटे बाहरी उपचारों से हमारा जीवन थोड़े ही सुखमय होने वाला है ।

एक ओर हमने धन को एकत्र करना एक प्रयोजन बना दिया, दूसरी ओर हम चाहते हैं कि पूंजीपति व्यक्ति परोपकारी हों और एक सीमा से अधिक धन अर्जित न करें । इस सीमा की भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है । यह धन सभी के पास उपलब्ध नहीं है और धन के बिना संसाधनों को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है । पूंजी पर अधिक नियंत्रण करना एक ज़रुरत बन गयी है और वह सबके पास न होने के कारण अनजाने ही हमारे जीवन में असमानता, अन्याय ,वैमनस्य और द्वन्द पैदा हो गए हैं । **यह अर्थशास्त्र के मौजूदा मॉडल का मौलिक विरोधाभास है** । यानिकि हम एक कदम आगे रखना चाहते हैं और एक कदम पीछे भी आना चाहते हैं । ठीक से कुछ भी सोच समझ के निश्चित नहीं किया गया , कि किस तरफ जाना है , सबकी समृद्धि की तरफ या असमानता बढ़ा के मारधाड़ की तरफ । मौलिक रूप से हम सभी ने एक अन्यायपूर्ण प्रणाली को अपनाया है , फिर भी दूसरी ओर हम परिधीय उपायों द्वारा अधिक समता और न्याय लाने के प्रयास कर रहे हैं । यह हमारे सिस्टम में अन्तर्निहित और अंतत: हमारे जीवन में परिलक्षित अंतर्विरोध है ।

इस दुष्चक्र से मानव समाज कभी भी ठीक से समृद्ध नहीं हो सकता है । कुछ पॉकेट्स अत्यधिक अमीर होंगे और अधिकाँश गरीब । उलझन बनी रहेगी और हम सब लड़ते झगड़ते रहेंगे । हम सब यह होता हुआ देख ही रहे हैं । इस प्रमुख विरोधाभास से कई अन्य परिणामी खामियां भी उत्पन्न होती हैं ।

धन की शर्त से असमानता एवं अन्याय क्यों होता है ?

बाजार में मांग के लिए धन की अनिवार्यता , मांग और आपूर्ति द्वारा संचालित मूल्य के सिद्धांत को स्वतः ही जन्म देती है । माल, सेवाओं और श्रम का मूल्यांकन , मांग और आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होना स्वाभाविक हो जाता है । धन की शर्त प्रणाली को पूंजीवादी बनाती है , और शक्ति केंद्र को जन्म देती है । मूल्य प्रणाली आय और धन के वितरण में असमानता को जन्म देती है । मूल्यतंत्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकता है , बल्कि यह आय और धन के वितरण में असमानता को बढ़ाता है जिससे सभी प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं । आइये समझते हैं कैसे।

सामूहिक रूप से स्वीकृत यह नियम है की मांग करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए । बार्टर इकोनॉमिक्स (वस्तु विनिमय प्रणाली) में भी कुछ ऐसा ही नियम मौजूद था । किसी दूसरे की वस्तु प्राप्त करने के लिए , बदले में कुछ उत्पाद या सेवा देने की आवश्यकता होती थी । इसलिए ऐतिहासिक रूप से हमने हमेशा समाज जनित सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इस शर्त का पालन किया है । आदिम समाज में भी किसी न किसी तरह का आदान-प्रदान अनिवार्य माना गया है । इस नियम को न्याय का, सभ्यता का पर्याय भी माना जाता रहा है । लेकिन वास्तव में, अन्याय की शुरुआत इसी नियम से होती है। इस नियम के कारण सामाजिक व्यवस्थाएं हमेशा अपर्याप्त रही हैं । इसी बिंदु पर व्यवस्था प्रतिद्वन्दात्मक हो जा रही है जबकि हमें एक सहयोग तंत्र की आवश्यकता थी ।

अब आप पूछ सकते हैं की आखिर स्वैच्छित वस्तु विनिमय या पैसे के द्वारा लेन देन अन्यायपूर्ण कैसे हो सकता है , इससे क्या दुष्परिणाम होगा ? कुछ लोग यह पूछ सकते हैं , मनुष्य फ्री में तो भोगना नहीं चाहिए । पहले वह कुछ बनाये , पुरुषार्थ करे और फिर बदले में भोगे । यह तो जायज़ सी बात लगती है । अगर सब फ्री में मिल जायेगा तो मेहनत कौन करेगा आदि ?

लेकिन मूल सवाल तो यही है की आखिर वह बनाये तो बनाये क्या ? किस चीज़ का उत्पाद करे ? यह उसे कैसे पता चलेगा ? संसाधन एवं पूँजी कहाँ से आएंगे ? टेक्नोलॉजी एवं ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए पूँजी कहाँ से आएगी ? बनाने के बाद कहाँ उसे बेचेगा , कितने पैसे में बेचेगा और कौन खरीदेगा ? **विनिमय न्यायपूर्ण है, इसकी कसौटी क्या है ?** अगर हम केवल एक विनिमय के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके न्याय संगत , निष्पक्षता , स्वतंत्रता और मेहनत की दुहाई देंगे तो यह वाजिब नहीं होगा । हमें शुरआत से अंत तक पूरी प्रक्रिया को देखना होगा । और पूरी प्रक्रिया जायज़ होनी चाहिए , सोची समझी होनी चाहिए , सुनियोजित होनी चाहिए , और इच्छित परिणाम होने चाहिए सभी के लिए ।

लेकिन बाजार प्रक्रिया में वास्तविक मांग और कितने लोग उसका उत्पाद कर रहे हैं , इसका ठीक-ठीक पता नहीं होता । जब वास्तविक मांग अज्ञात है तो श्रम , उत्पाद और सेवाओं की अनियंत्रित अधिकता और कमी होगी । इस प्रकार मूल्यांकन में भी काफी भिन्नता और उतार-चढ़ाव होगा । व्यक्तिगत रूप से सब इसी होड़ में लगे हैं कि किसी तरह बाजार पर नियंत्रण आ जाये । यहां मानव संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का सभी के लिए सोचा समझा प्रबंधन नहीं किया जा रहा , बल्कि बाजार में कार्यरत विभिन्न बलों और कारकों की परस्पर क्रिया द्वारा अनियंत्रित निर्धारण हो रहा है, जो एक केन्द्रीगत प्रबंधन के अंतर्गत नहीं हैं। इस प्रणाली में जीवन बाजार की अराजकता का परिणाम है । इसलिए कहा जाता है कि यहां कुछ भी हो सकता है । यहां किसको क्या मिलेगा यह सोचे समझे नियोजन द्वारा नहीं हो रहा बल्कि बाजार के अप्रत्याशित गतिशीलता के अधीन होता है । व्यवस्था व्यक्ति को समर्थ नहीं कर रही , व्यवस्था उसे कह रही है , तुम पहले अपनी पात्रता स्थापित करो और पात्रता का प्रमाण पैसा है । और पैसा मिलेगा बाजार में प्रभुता हासिल कर के और जबकि पैसा सबके पास समान हो नहीं सकता ।

यदि हमारे अर्थशास्त्र में पूर्व शर्त के रूप में पैसा है , तो धन का कुछ लोगों के हाथ में जमा होना अपरिहार्य है । एक बाजार अर्थव्यवस्था में , एक वोट मतपत्र द्वारा नहीं बल्कि धन शक्ति द्वारा डाला जाता है ।आपके पास जितना पैसा होगा , मौजूदा बाजार सिस्टम में उतनी ही अधिक वोटिंग शक्ति होगी । चूंकि ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा हर किसी के पास समान रूप से यह मतदान शक्ति हो , इसलिए लोग धन प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में प्रवेश करते हैं , या दूसरे शब्दों में बाजार को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते हैं और एक शक्ति संघर्ष शुरू होता है । इस प्रकार , धन वोट महत्वपूर्ण हैं । उच्च आय वाले लोगों में गरीबों की तुलना में अधिक मतदान शक्ति होती है । इसलिए जिसके पास अधिक धन है, उसका अमीर बने रहना ज़्यादा आसान है । अंततः धन एक ऐसी वस्तु बन गया है जिसे अन्य प्रकार के प्रयासों द्वारा हासिल करने की आवश्यकता हो जाती है । हमने एक ऐसी प्रणाली चला रखी है जिसमें बाजार की मूल्याङ्कन विधि हमारे जीवन की स्थिति को निर्धारित करता है ।

बाजार तय करता है कि कौन सा श्रम अन्य की तुलना में अधिक मूल्यवान है । और ज़ाहिर सी बात है जिसका मूलयांकन कम होगा वह मेहेंगी चीज़े नहीं खरीद सकता । **इस तरह से हम अनिवार्य रूप से एक शक्ति केंद्र का निर्माण करते हैं ।**

वास्तविक दुनिया में, आदर्श बाजार एक कल्पनामात्र है। उपभोक्ता की संप्रभुता असत्य है। विक्रेता कीमतों को अपने मुनाफे के लिए प्रभावित करते हैं । एक मुक्त, अनियमित मूल्याङ्कन प्रणाली में अस्थिरता पैदा होना लाजमी है । इसका मतलब है कि व्यापर में उत्कर्ष (Boom) और मंदी (recession) आते जाते रहेंगे । विकास की दर, निवेश, मूल्यस्तर, रोजगार आदि, एक क्रमिक ढंग से उतार-चढ़ाव करते रहेंगे । यह उतार चढ़ाव अर्थशास्त्र में अन्तर्निहित असमानता का नतीजा है। आर्थिक गतिविधियों के स्तर में इस तरह के उतार-चढ़ाव हो रहे सामाजिक-आर्थिक अन्याय को ही विकसित करते हैं ।

आर्थिक असमानता परिणाम स्वरूप अन्य सभी असमानताओं को फलित करेगी। इस असमानता को आप होने से कैसे रोक लोगे? इन असमानताओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अपराध होंगे। तो यह न्याय कैसे हो सकता है? इसे एक न्यायसंगत और सुव्यवस्थित प्रणाली कैसे कहा जा सकता है, यदि स्पष्ट परिणाम है कि जनता एक अच्छा जीवन नहीं जी सकती है? हमारी अपनायी आर्थिक प्रणाली एक सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित नहीं है जो सभी मनुष्यों के लिए स्वीकार्य हो। यह ढांचा उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है जिसके लिए हमने एक व्यवस्था की कल्पना की थी। हम उस मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं जिसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है । मूल में प्रत्येक मनुष्य इच्छित ज्ञान, इच्छित कर्म और इच्छित भोग का आनंद लेना चाहता है। और इसी को प्राप्त करवाए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मनुष्य तो ऐसी मेहनत, ऐसा काम स्वतः ही करना चाहता है, जो उसके अनुकूल हो। उसी में उसको रस आता हो और उसी में उसको सफलता भी मिलेगी। जब वह अपने काम में सफल होगा तो उसका फायदा समाज उठाएगा । लेकिन मौजूदा व्यवस्था इसी बात को व्यवस्थित नहीं कर पा रही और लोगों को एक दूसरे से भिड़ा रही है। वास्तव में जीवन में आनंद एक सामाजिक परिणाम है और इसलिए हमारे जीवन की सफलता सभी की इच्छाओं की सामंजस्यपूर्ण पूर्ति पर टिकी हुई है।

प्रतिद्वंदितापूर्ण अर्थशास्त्र का मूल कारण

प्रत्येक प्रणाली को एक आधार, एक दर्शन की आवश्यकता होती है, जिस पर वह संचालित होता है। मौजूदा अर्थशास्त्र मुख्य रूप से इस आधार पे बना है कि मानव की चाहतें अनंत है और संसाधन सीमित हैं । व्यापक धारणा यह है कि पृथ्वी में संसाधनों की कमी है और मूल्यतंत्र संसाधनों की राशनिंग के लिए एक प्रभावी उपकरण है । इस बात को बिना जांचे परखे यह बात मान ली जाती है की संसाधन सबके लिए पर्याप्त नहीं हैं । इसी से सारी प्रतिद्वंदिता का जन्म हो जाता है । यह एक मूलभूत दोष है और लेखक इस बुनियादी , सबसे मौलिक अर्थशास्त्र की धारणा से इत्तिफाक़ नहीं रखते । हमारी खोज के अनुसार यह एक गलत फहमी है कि मानव अनंत चाहतें रखता है । इसके बारे में एक दुसरे लेख में विस्तार से चर्चा की है । **कमी, बहुतायत या पर्याप्तता उस काल में उपलब्ध टैकनोलजी और प्रबंधन मॉडल पर निर्भर करती है और सामाजिक-सांस्कृतिक आधार रखती है।**संक्षेप में , हमारी खोज के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं सीमित हैं, इच्छाओं का समुच्चय एक फ्रेम के भीतर चक्रीय रूप से दोहराता है । प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं का अपना ढांचा होता है जो परिमित होता है । दैनिक जीवन में इच्छाओं की भिन्नता एवं बदलना एक सीमा के भीतर है। इस फ्रेम का दायरा या स्वरूप चेतना के स्तर से निर्धारित होता है । मानव चेतना अपनी इच्छा से , प्राकृतिक विकास क्रम में अपने फ्रेम को बदलती है लेकिन वह हमेशा एक फ्रेम के भीतर ही काम करेगी । किसी भी समय कोई भी व्यक्ति असीमित इच्छाएं नहीं करता है और ना ही सब कुछ चाहता है । पृथ्वी पर संसाधन हमारी इच्छाओं के लिए पर्याप्त हैं।

यह भी बड़े आश्चर्य की बात है की आज की दुनिया में हर एक वस्तु के लिए दुर्लभता का नियम लागू कर दिया जाता है । और सभी संसाधनों, उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन और वितरण मूलयांकन विधि द्वारा किया जाता है । अगर कोई संसाधन दुर्लभ है , जिसका अभाव है तो केवल उसी का मैनेजमेंट अलग ढंग से हो, सभी संसाधानों पर आखिर क्यों दुर्लभता का नियम थोपा जा रहा है? दुनिया में पर्याप्त संसाधन हैं और किसी एक समय मनुष्यों की परिमित इच्छाएँ हैं। दोनों संसाधन और मानवीय इच्छाएं इस अभूतपूर्व अस्तित्व में चक्रीय फैशन में चल रही हैं । इसलिए सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणाली में संभव है ।

तार्किक रूप से तो पहले मांग का ज्ञान होना चाहिए और फिर आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए । लेकिन वर्तमान आर्थिक प्रणाली में माल को पहले बाजार में जमा किया जाता है , और फिर विक्रेता इसे बेचने के लिए इंतजार करते हैं , मांग की प्रत्याशा में । उत्पादक अनुमान के आधार पर जोखिम उठाते हैं । इसके अलावा कई प्रतियोगी उपभोक्ताओं पर प्रभुता हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं । इससे बाजार गैर-मानकीकृत (non standardized) उत्पादों के निर्माण की ओर जाता है । इससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक अपव्यय भी होता है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन (optimization) और मानकीकरण (standardization) के लिए केंद्रीकृत प्रबंधन नहीं है । इसलिए संसाधनों का वाजिब प्रबंधन करने के बजाय हम अधिक अपव्यय करते हैं जिससे बनावटी अभाव पैदा होता है। संसाधन कम पड़ जाते हैं क्यूंकि हमारी मैनेजमेंट में कमी है नाकि प्रकृति में ।

नया अर्थशास्त्र

मैं एक नई गैर-मौद्रिक, बाज़ार रहित आर्थिक प्रणाली का प्रस्ताव रख रहा हूं जिसमें नागरिकों के बीच कोई विनिमय नहीं है। कृपया ध्यान दें, यह न तो गिफ्ट इकॉनमी है और न ही यह समाजवादी कमांड अर्थव्यवस्था है। बल्कि **नए मॉडल में, हम सभी लोगों की ज़रूरतों को जान सकेंगे और एक केन्द्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से मांग के अनुसार उत्पादन का प्रबंधन कर सकेंगे।** सभी के व्यक्तिगत मांग का वैज्ञानिक एवं गणितीय विधियों द्वारा केन्द्रीगत संकलन होगा एवं आपूर्ति के लिए केन्द्रीगत संसाधन प्रबंधन । इस विकेंद्रीकृत-केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से पूरी मांग एकत्र की जाएगी, और एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत सारे आर्थिक क्रियाकलाप होंगे।

नई व्यवस्था में मांग रखने के लिए पैसे की कोई शर्त नहीं है। मैं पैसे और मांग के अधिकार के बीच की मौजूदा कड़ी को तोड़ने का प्रस्ताव रख रहा हूं। नई व्यवस्था में पैसा नहीं है और बाज़ार द्वारा मूल्यांकन मौजूद नहीं होगा। अगर हम पैसा रखते हैं तो यह अपरिहार्य है कि धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और कई तरह की समस्याएं पैदा करेगा। **इसलिए मैंने मुद्रा हटा दिया है और 25-50 वर्ष के बीच के वयस्क व्यक्ति के लिए एकमात्र शर्त यह है कि वह किसी प्रकार का रोज़गार लेकर व्यवस्था में भाग लेता रहे।** समाज में उनके योगदान के लिए नागरिकों को अलग-अलग महत्व नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक पेशे को समान रूप से महत्व दिया जाएगा और सभी नागरिक अपने प्रोडक्ट और सर्विस आर्डर को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे, जिसमें वर्गीकृत प्रोडक्ट / सर्विस कोड होंगे।

इस नीति द्वारा, उत्पादों और सेवाओं की अधिकतम संभव मांग पैदा होगी जो के रियल-टाइम जाना जाएगा और आर्थिक नियोजन में सब्ज़े ज़्यादा मददगार साबित होगा। अधिकतम संभव मांग की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हमें कारखानों, मशीनों, सड़कों, परिवहन आदि जैसे अधिकतम संभव बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। (नीचे चित्र देखें)

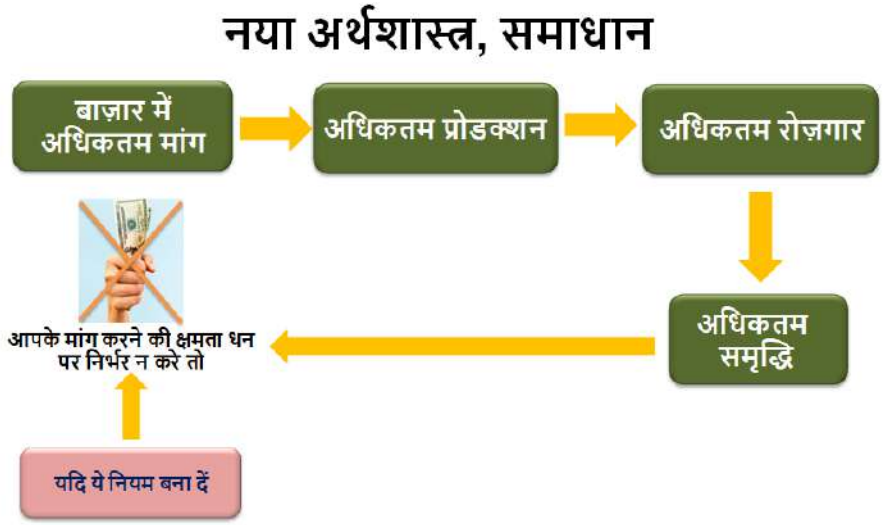

इस सारे उत्पादन और वितरण प्रबंधन के लिए हमें अधिकतम मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो सरल शब्दों में, हम सिर्फ एक साधारण बदलाव से अधिकतम संभव रोज़गार की गुंजाइश पैदा करेंगे।

इस पुण्य चक्र के कारण पूर्ण रोज़गार से सभी सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हम सभी समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लोग वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव तभी कर सकते हैं जब सभी को समाज की सह-निर्मित समृद्धि का समान रूप से लाभ उठाने का अधिकार हो।

लेखकों का कहना है कि मानव एक अतार्किक प्राणी नहीं जो सीमित संसाधनों की दुनिया में अनंत इच्छाओं का पीछा करता फिरेगा। मानवचेतना मौलिक रूप से अतार्किक, हिंसक या पागल नहीं है अपितु मानव व्यवहार व्यवस्था का प्रतिबिंब है। अगर कोई पागलपन करता है, हिंसा करता है, अत्यधिक एकत्र करता है तो वह भी व्यवस्था में अन्तर्निहित असुरक्षा का दोष है। यह मौजूदा प्रणाली या ढांचा है जिसने हमें प्रतिस्पर्धा में डाल दिया है और एक नई प्रणाली है जो हमें सहयोग में डाल सकती है।

नए अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है ?

अर्थशास्त्र **optimal** संसाधन प्रबंधन है जो मानव प्रकृति की समझ का उपयोग करते हुए, सुख के कारकों का input करते हुए, सभी के लिए सुख के लक्ष्य को अधिकतम करने के लिए योजना पद्धति एवं तकनीक बताता है।

'अर्थशास्त्र' शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है। शास्त्र का अर्थ - किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यो के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। अब, अर्थ क्या है? सुख के लिए सामाजिक प्रयास से सांस्कृतिक रूप से जो कुछ भी बनता है उसे अर्थ के रूप में जाना जाता है।

जो भी उत्पाद और सेवाएं हमारे लिए सुख पैदा करती हैं, उन्हें अर्थ के रूप में जाना जाता है। ज्ञान जो सुख पैदा करता है, जो कार्य (कर्म) हमारे लिए सुख पैदा करता है, जो उत्पाद / सेवाएं (भोग) हमारे लिए सुख पैदा करते हैं, वह सब अर्थ है। पर्यावरण, सुविधाएं जो हमें कार्य करने और विश्राम लेने के लिए सक्षम बनाती हैं उसे भी अर्थ कहते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, समाज और पर्यावरण स्तर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अर्थ के मांग, उत्पादन और वितरण प्रणाली को अर्थशास्त्र कहते हैं। सरल शब्दों में, अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जो हमें अपनी इच्छाओं को रखने का सिस्टम आधारित तरीका देती है, उन इच्छाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है जिससे प्रोडक्शन हेतु उचित संसाधन आवंटन हो और एक वितरण व्यवस्था ताकि नागरिक लगातार अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर सकें। अर्थ भी मूल्य का पर्याय है और इसलिए अर्थशास्त्र मूल्य सृजन के लिए संसाधन प्रबंधन है।

- ## नयी व्यवस्था में संसाधनों पर कोई निजी स्वामित्व नहीं है

सभी संसाधन व्यवस्था के पास रहेंगे, अर्थात् मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों। मांग के अनुसार उत्पादन के लिए, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का संजोग करके सभी की इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। एक इंटेलीजेंट डिज़ाइन के तहत, लोग अपनी मांगो को पूरा करने के लिए ख़ुद ही अपना इच्छित काम करेंगे। यह व्यवस्था मनुष्य स्वार्थ के अनुसार है, इसलिए मनुष्य को सबसे सुगम रास्ते उसके इच्छित सुखों तक पहुंचाती है।

- ## नई आर्थिक व्यवस्था केंद्रीय रूप से नियोजित है

सभी नागरिकों के सुखों को एक केंद्रीय नियोजित आर्थिक मॉडल का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है जो बदलती प्राथमिकताओं, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के अनुकूल हो सकेगा। यह केंद्रीय रूप से नियोजित मॉडल सबसे अधिक responsive डिज़ाइन है और मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करता है। नागरिक तय करेंगे कि वे क्या चाहते हैं लेकिन केंद्रीय प्लानिंग का उपयोग उत्पादों / सेवाओं के मानकीकरण और कुशल उत्पादन और वितरण के लिए किया जायेगा।

- ## सभी की एक डिजिटल प्रोफ़ाइल होगी

इस व्यवस्था में सभी का ऑनलाइन प्रोफाइल होगा जिसमें उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी आयु, उनका फोटो, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, आदि आदि।

- **आप बिना पैसे के ऑर्डर दे सकते हैं**

विभिन्न उत्पादों / सेवाओं के लिए लोग अपना ऑनलाइन खाता बना सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए भी सरल प्रक्रिया और सहायता उपलब्ध होगी। सभी कुछ मांग करने के लिए यह केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम ही होगा।

- **सभी सुखों को परिभाषित कर आर्थिक लक्ष्य तय किये जाएंगे**

नागरिकों के व्यक्तिगत सुखों को एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वांछित उत्पादों / सेवाओं में अनुवादित किया जाएगा और फिर एक गणितीय पद्धति द्वारा आर्थिक लक्ष्यों में अनुवादित किया जाता रहेगा। यह अनुवाद यूएलएम द्वारा बनाए गए मानव प्रकृति के सुख के मॉडल पर आधारित होगा ।

- **नागरिक अपनी मांग सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज़ कर सकते हैं**

सभी की मांग व्यवस्था तक निरन्तर पहुँचती रहेगी और ऑर्डर के क्रम से व्यवस्था उत्पादों का निर्माण और डिलीवरी करती रहेगी। केंद्रीय योजना गणितीय formulations द्वारा एवं नागरिकों एवं वर्कर्स के real-time data input के आधार पर संभव हो सकेगा। व्यक्तिगत चाहतों का प्रत्यक्ष फ़ीड न केवल socialist calculation debate को SOLVE कर देता है, बल्कि मांग के पूर्वानुमान के लिए सही शुरुआती बिंदु भी है। अगर सिस्टम नागरिकों से यह नहीं पूछता कि वे क्या चाहते हैं तो कोई सिस्टम कैसे जान सकता है कि क्या उत्पादन करना है? अब तक, किसी भी आर्थिक मॉडल ने नागरिकों को उनकी इच्छाओं को पेश करने तक की अनुमति नहीं दी, चाहे वह समाजवादी कमांड अर्थव्यवस्था हो या बाज़ार अर्थव्यवस्था। न ही इन मॉडल्स में स्पष्ट समझ थी कि सुख क्या होता है, इसलिए कोई फॉर्मेट भी न तैयार कर सके यह जानने के लिए की पब्लिक वास्तव में क्या चाहती है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले के व्यवस्थापकों ने कभी भी जनता के लिए संपन्नता की संभावना नहीं बनाई और और यह अलोकतांत्रिक बात है।

कीमतों के बिना एक नया अर्थशास्त्र लेकिन एक नए तरह का मापन रहेगा

नई आर्थिक प्रणाली में बाज़ार मूल्यांकन नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं पर कीमतें नहीं हैं, लेकिन व्यक्तिगत सुख को अधिकतम करने के लिए संसाधनों के प्रबंधन हेतु गैर-मौद्रिक गणितीय माप होंगे। आर्थिक गतिविधियों की निगरानी के लिए इन मापों का इस्तेमाल होगा।

बाज़ार मूल्यांकन के बिना एक नया अर्थशास्त्र

नई आर्थिक प्रणाली धन विहीन या गैर-मौद्रिक है। वस्तुओं और सेवाओं की कोई कीमत नहीं है। व्यक्ति को उत्पादों/सेवाओं के लिए ऑर्डर देने के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी को उस काम के लिए कोई वेतन मिल रहा है जो वह करता है। यह नया अर्थशास्त्र इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है की जितने मूल्य का काम किया उतना मूल्य आपको मिलना चाहिए। क्यूंकि ऐसे मूल्याङ्कन का कोई वास्तविक आधार नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कोई मूल्याङ्कन नहीं रखा गया। ऐसे झूठे मूल्याङ्कन से उंच नीच ही पैदा होगी। जब हम पैसे की ऐसी पूर्व शर्त लगाते हैं, तो हम उस मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं जिसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

बाज़ार मूल्याङ्कन प्रणाली से हम मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं के प्रत्येक मानव एक सुरक्षित वातावरण में इच्छित ज्ञान, कर्म, भोग और विश्राम का सुख लेना चाहता है। पैसे की पूर्व शर्त से, हम मनुष्य को उसकी इच्छाओं को पूरा करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हम उसे सक्षम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे जीवन के सुख भोगने के लिए कीमत चुकाने को कह रहे हैं। व्यवस्था उसकी इच्छाओं की पूर्ति की सुविधा नहीं दे रही है, बल्कि सभी मनुष्यों को मांग करने से पहले अपने अधिकार अर्जित करने या मूल्य अर्जित करने को कह रही है। यह मूल समस्या है। सभी मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यवस्थागत प्रबंधन के बजाय मौजूदा अर्थशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु विकल्प की दुविधा है जो संसाधनों की कमी की कल्पना के कारण उत्पन्न होती है। यह गलत

धारणा है कि मनुष्य की असीमित इच्छाएँ होती हैं लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के साधन सीमित हैं। इसलिए, हम गलत तरीके से मानते हैं कि सीमित साधनों के साथ सभी मानवीय इच्छाओं को पूरा करना असंभव है और इसलिए अर्थशास्त्र ट्रेड-ऑफ की बात करता है। अर्थशास्त्र कहता है आप क्या खोने के लिए तैयार हो कुछ पाने के लिए? क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? इस लिए अर्थशास्त्र विकल्पों के बारे में एक विषय बन जाता है और विकास की गलत परिभाषा के साथ अंधी दौड़ में लग जाता है जहां इंसान के सुख केंद्रीय लक्ष्य नहीं। यह एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जाता है जहाँ जनता अपनी साधारण इच्छाओं को पूरा करने के योग्य नहीं बचती और केवल कुछ ही लोग पृथ्वी के संसाधनों के स्वामी बने फिरते हैं।

नयी व्यवस्था का ज़ोर व्यक्ति को उसका इच्छित सुख प्रदान करना है और यह तुलना करना नहीं कि कौन अधिक योग्य है। इस व्यवस्था में, प्रत्येक प्राणी जो चाहता है उसका हकदार है। व्यवस्था लोगों के लिए बनाई गई है और लोगों को अनिच्छा से किसी शोषणकारी व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुविधा प्रदान करेगा, आपको सिस्टम का गुलाम होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं उसे जीने के लिए आपको मूल्य (मूल्य के माप के रूप में धन) अर्जित करने या अधिकार अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। सारे अधिकार आपको जन्म से ही मिलेंगे।

आपको सुखों का हक़दार होने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी, धन एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं। यदि व्यवस्था नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं बनाती है, खासकर यदि यह स्पष्ट है कि उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, तो इसे एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में घोषित किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि व्यवस्था हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने में सक्षम बना रही है, तो यह एक न्यायसंगत व्यवस्था है। 25-50 वर्ष की आयु के बीच के वयस्क व्यक्ति के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि वह किसी न किसी रूप में रोज़गार लेकर व्यवस्था में भाग लेता रहे। इस सहयोग के बिना उसे पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। अत: उसे अपनी रुचि का कार्य चुनकर जीवन के सारे मज़े मिलते रहेंगे।

सभी रोज़गार का समान मूल्य होगा

नई व्यवस्था को इस तरह से रचा गया है जो सभी प्रकार के व्यक्तित्वों के लिए उनके प्राकृतिक रुचियों के अनुसार सुखद, सार्थक और सुविधाजनक जीवन को सक्षम बनाता है। व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि व्यक्तित्व अपने स्वार्थ का पीछा करते हुए स्वचालित रूप से एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे और समान रूप से मूल्यवान होंगे।

आर्थिक नियोजन का आधार

यूएलएम की खोज मानव चेतना के आतंरिक प्रक्रिया को परिभाषित करती है और यह ज्ञान, सिस्टम डिज़ाइनरों को सुख सुविधाओं का एक व्यापक फ्रेम स्थापित करने में सक्षम बनाता है। चेतना के ज्ञान पर आधारित एक सर्वस्वीकृत system development program के अंतर्गत सुखों का फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें विशिष्ट विकल्प नागरिक स्वयं पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत मांग रखते हुए करेंगे। ये लाइव इनपुट मांग forecast तैयार करने में मदद करेंगे। एक बार जब व्यक्तिगत इच्छाओं को objective लक्ष्यों में बदल दिया जाता है, तो यह नेताओं को मापन योग्य लक्ष्यों पर कार्य करने और गणना करने में मदद करेगा और प्लानर्स आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गणना कर सकेंगे। आर्थिक नियोजन के तीन स्तर होंगे - detailed plan, strategic plan और macro-economic plan.

अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या

अगर मूल्य तंत्र नहीं तो आर्थिक गणना क्या है और कैसे होगी ? मनुष्य की चाहतों, सीमित संसाधनों और विशिष्ट बाधाओं के आधार पर planning problem formulate होगा जिसका एक optimal लक्ष्य होगा। आर्थिक लक्ष्य तय किया जायेगा ULM के हैप्पीनेस मॉडल पे आधारित एक गणितीय विधि द्वारा। आर्थिक गणना अनिवार्य रूप से उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक planning problem है और इसमें गणित की विभिन्न शाखाएँ, systems और control के सिद्धांत, स्व-शिक्षण और होमिओस्टेटिक तंत्र, सर्वो तंत्र और ऑटोमेटा, सूचना और निर्णय लेने के सिद्धांत, गणितीय linear programming व optimization के सिद्धांत को इस्तेमाल किया जायेगा। योजना का गणितीकरण, दिए गए प्राकृतिक बाधाओं के तहत उपलब्ध संसाधन विकल्पों के साथ happiness function को अधिकतम करेगा। सिस्टम material balance planning विधि और ऐसे algorithms का उपयोग करेगा

जो विभिन्न वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को इनपुट करता हुआ और सुख के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गणित और विभिन्न अन्य विज्ञानों, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन आवंटन का optimal हल निकालता हो।

कीमतों के बिना कोई आर्थिक निर्णय कैसे ले सकता है?

- **अर्थशास्त्र का मौजूदा प्रतिमान-**

अभाव की परिभाषा सभी सामान पर लागू होती है जहां उस सामान की एक इकाई का उपयोग करने का निर्णय कुछ अन्य संभावित उपयोग को छोड़ना होता है। इस प्रकार वैकल्पिक उपयोगों के बीच एक उपयोग का चुनाव होता है, और चुने गए किसी भी उपयोग के लिए एक opportunity cost है। Opportunity cost का मतलब है उन वैकल्पिक उपयोगों के बीच में से सबसे अच्छा उपयोग जिसे चुना नहीं गया, इस प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कि चुने गए उपयोग को चुना गया था। अगर मेरे पास ज़मीन का एक प्लॉट है, और मैं इसे गोल्फ कोर्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, और अगर गोल्फ कोर्स के लिए इसका इस्तेमाल करने के अभाव में इसका इस्तेमाल आम उगाने के लिए किया जाएगा, तो यह जमीन दुर्लभ है, और बिन उगाए आम हैं गोल्फ के खेल की cost। अभाव के बिना कोई cost नहीं है; बिना cost, कोई अभाव नहीं। इस प्रकार किसी को आश्चर्य हो सकता है कि बिना कीमतों के कोई आर्थिक निर्णय कैसे ले सकता है। आखिरकार, costs सामान्य इकाई हैं जो विभिन्न विकल्पों की तुलना करने में मदद करती हैं।

- **अर्थशास्त्र का नया प्रतिमान-**

नए प्रतिमान में, अर्थशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु अभाव नहीं है। प्रारंभिक बिंदु मानव चाहतें हैं। तो मांग का आंकलन किया जाएगा, उदाहरण के लिए : यह निर्धारित करने के लिए कि कितने गोल्फ कोर्स और कितने टन आम के उत्पादन की ज़रूरत है। इस उत्पादन के कई तरीके हो सकते हैं और यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, हम कीमतों का उपयोग नहीं करेंगे। कीमतें हमें यह जानकारी नहीं देती हैं कि किसी विशेष प्रक्रिया को चुनना समाज के लिए अधिक फायदेमंद क्यों है और कोई अन्य प्रक्रिया कम फायदेमंद क्यों है। cost efficient होने का मतलब यह नहीं है कि यह सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि cost में समाज के लिए सुख पैदा करने वाली जानकारी शामिल नहीं है। यद्यपि मूल्य तंत्र के लिए उद्धृत उद्देश्य यह है कि यह सामाजिक लक्ष्य के लिए सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में मदद करता है लेकिन परिणाम एक अलग कहानी बताते हैं। हर कोई किफ़ायती होने की कोशिश कर रहा है फिर भी लोगों की दुर्दशा यह है कि अधिकांश ग़रीब दुखी हैं और पर्यावरण की खस्ता हालत है। अब मूल्य निर्धारण के बजाय कोई कैसे जान सकता है कि कौन सा तरीका आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है। कौन सा तरीका मनुष्य को केंद्र में रख कर अधिक लाभप्रद है ?

इसलिए नए प्रतिमान में व्यक्तिगत सुख यानी हम मनुष्य जो चाहते हैं, उसको सामाजिक उद्देश्य रूप में आर्थिक लक्ष्यों में अनुवाद किया जायेगा और इसमें अन्य प्राकृतिक बाधाएं शामिल होंगी (विज्ञान के हमारे ज्ञान के आधार पर जैसे पर्यावरण पर प्रभाव आदि)। इन बाधाओं को गणितीय समीकरणों में डाल कर और इन समीकरणों को वांछित लक्ष्यों के लिए संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने के लिए हल किया जायेगा। इस प्रकार ऐसे उद्देश्य के लिए विकसित गणित और एल्गोरिदम का उपयोग करके आर्थिक निर्णय लेना होगा ताकि हम अपने सभी विचारों और बाधाओं को दर्ज कर सकें और नागरिकों के सुख को अधिकतम करने के लिए सबसे optimal तरीका खोजने के लिए इसे हल कर सकें। मनुष्य को ज्ञात सभी सुख के कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी गणना के अलावा ज्ञान आधारित निर्णय लेने का कोई अन्य तरीका तो दिखता नहीं है। इस प्रकार ऐसे उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा आर्थिक गणना एवं निर्णयों के लिए किया जाएगा जो विभिन्न विकल्पों के चुनाव को simulate कर तुलना करने में मदद करेगा और इस तरह संसाधन आवंटन के संबंध में सही विकल्प चुन पाना संभव हो सकेगा। **तो अर्थशास्त्र का विषय cost-efficiency के बजाय optimality की गणना करने की समस्या बन जाता है।**

गुणवत्ता और दक्षता को कैसे बनाए रखा जा सकता है?

गुणवत्ता और दक्षता इसलिए संभव है क्यूंकि सभी अपनी गहरी रुचियों और योग्यता के हिसाब से काम कर रहे होंगे। जब यह व्यवस्था पूरी तरह से स्थित हो जाएगी तो लोगों को उनकी अभिरुचि अनुसार ही काम मिलेगा और इच्छा का काम करना सबको पसंद आता है। जब काम करने में मज़ा आता है तो हर आदमी स्वाभाविक रूप से अपना बेस्ट देता है। जब किसी व्यक्ति से

सबसे अच्छा निकलता है तो वह qualitative वस्तु व सेवा के रूप में परिणित होगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था में भाग लेने से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम संभव incentive और अर्थ मिलता है। क्या पूरी तरह से सुखमय जीवन से बड़ा कोई incentive हो सकता है?

हर कामग़ार अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्था द्वारा प्रदान production target को हामी देगा। सिस्टम किसी को उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। प्रत्येक कार्य दिवस में अनुमानित 4-5 घंटे का कार्य होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होगा, जिसे धीरे-धीरे करने पर भी प्राप्त करना संभव होगा। हर कोई अपनी गति के अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। सिस्टम केवल अंतिम आउटपुट और इसकी गुणवत्ता के बारे में चिंतित है। आप कितने तेज या धीमे हैं इससे कोई सरोकार नहीं है। आपको बस एक उचित समय सीमा के भीतर अपने पूर्व-निर्धारित, स्व-अनुमोदित उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना होगा। यह एक ऐसा माहौल तैयार करेगा जहां हम एक-दूसरे पर पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं। लोगों को मजबूर नहीं किया जा रहा है और उन्हें काम पर खतरा महसूस नहीं होगा। लोग अपनी इच्छा से काम करेंगे और स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। हर आउटपुट की गुणवत्ता की अलग-अलग चरणों में जांच की जाएगी।

संतुष्टि रेटिंग

प्रत्येक व्यक्ति सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के दौरान अपने अनुभव के आधार पर मूल्यांकन कर सकता है। यह रेटिंग स्वचालित प्रणालियों द्वारा लगातार एकत्र की जाएंगी और उनका विश्लेषण किया जाएगा। चूंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, इसलिए जब जनता किसी वस्तु/सेवा का उपयोग करेगी और यदि वह गुणात्मक नहीं है तो उसकी अंतिम समीक्षा नागरिकों की ओर से की जाएगी। यदि यह समीक्षा रेटिंग नकारात्मक आती है, तो उस अधिकारी/टीम/विभाग को सतर्क कर दिया जाएगा। तो जो जिम्मेदार होंगे उनसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ है, और विश्लेषण के बाद, उस समस्या का समाधान किया जाएगा और आवश्यक उपाय किए जाएंगे ताकि अंतिम उपयोगकर्ता संतुष्ट हो और वह समस्या फिर से न हो। इस तरह इस व्यवस्था में गुणवत्ता नियंत्रण होगा।

सम्पूर्ण समाधान प्रस्ताव को पूरी तरह से जानने के लिए किताब पढ़ें। धन्यवाद